

उद्योगों के विकास में सरकार का सहयोग बहुत जरूरी



आईआईए भवन में संगोष्ठी में बोलते पीटर रेकमन व मंचासीन अतिथि।

● अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मंगलवार को मध्यम और लघु एवं मध्य व लघु औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोगों के लिए प्रजेंटेशन का आयोजन किया। इसमें जर्मनी के अर्थशास्त्री व कंसल्टेंसी विशेषज्ञ पीटर रेकमन ने जर्मनी में कंसल्टेंसी के जरिए सरकार द्वारा उद्योगों को दिए जा रहे सपोर्ट पर अपने अनुभव साझा किए और उत्तर प्रदेश के लिए भी इनके आधार पर सुझाव दिए।

पीटर ने बताया कि वे जर्मनी के कोब्लेंज शहर से हैं। उनके प्रांत की आबादी 60 लाख है जो उत्तरप्रदेश में एक जिले की हो सकती है। उन्होंने अपने शहर में यूरोपियन यूनियन और जर्मन सरकार द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई

आईआईए भवन में जर्मन अर्थशास्त्री पीटर रेकमन ने बताया उद्योगों में कंसल्टेंसी का महत्व

एडवाजरी सर्विसेज के बारे में बताया, जिसमें कंसल्टेंसी फार्मों का 50 से 75 प्रतिशत तक का खर्च सरकार खुद देती है। इस तरह की कंसल्टेंसी में उद्योग की जरूरतों, कमजोरियों, सुधार, आदि के बारे में बताया जा रहा है। वर्ष 2011 में 18,188 इस तरह के मामले आए, जिनमें सरकार ने मदद दी। इस मौके पर आईआईए लखनऊ के चेयरमैन प्रशांत भाटिया, महासचिव मनीष गोयल और अरुणाचलम कार्तिकियन भी मौजूद थे।

उद्योगों को 50 फीसद तक आर्थिक मदद देती है जर्मन सरकार : रिचमेन

लखनऊ(एसएनबी)। जर्मनी के औद्योगिक संगठन जे.डी.हा सिक्वा के विशेषज्ञ पीटर रिचमेन ने मंगलवार को गोमती नगर स्थित इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में कहा कि जर्मनी की सरकार उद्योगों के विकास व उन्हें बढ़ावा देने के लिए 50 फीसद तक का आर्थिक सहयोग देती है। इस मौके पर उन्होंने कोब्लेन्ज डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के प्रारूप के विषय में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम के आरम्भ में आई.आई.ए के महासचिव मनीष गोयल ने जर्मन विशेषज्ञ का स्वागत किया। इस मौके पर जे.डी.हा सिक्वा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जर्मनी अरुणाचलम कार्तिकेयन ने भारत के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम के उद्देश्य के बारे में बताया। आई.आई.ए के अधिशाषी निदेशक डी.एस वर्मा ने एसोसिएशन की गतिविधियों व भविष्य की योजनाओं को बताया। सलाहकार सेवाओं के विशेषज्ञ पीटर रिचमेन ने एम.एस.एम.ई परामर्श की स्थापना व लोक प्रशासन की सहायता से एम.एस.एम.ई परामर्श में सुधार के बारे में विस्तार से बताया। जर्मन मॉडल के बारे में उन्होंने बताया कि कोब्लेन्ज डिस्ट्रिक्ट चैम्बर में 10 शहर शामिल हैं। इसमें उन्नीस हजार कंपनियां सदस्य हैं व 98 हजार 500 कर्मचारी तथा 250 चैम्बर कर्मचारी तथा 14 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। अन्त में उन्होंने बताया कि जर्मनी में कंपनियों को फंडिंग, गोथ कन्सोलिडेशन, सेल, विपणन, मानव संसाधन, निवेश इत्यादि की समस्याओं पर परामर्श उपलब्ध कराने में सहायक है।

श्री टाइम्स

लखनऊ • बुधवार • 12 दिसम्बर, 2012

सरकार उद्यमी संगठनों की मदद करनी करे

लखनऊ। जर्मनी में उद्यमी संगठनों को सरकार द्वारा लगभग 50 फीसदी सहायता प्रदान किया जाता है। वहाँ के संगठनों को किसी न किसी इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन से जुड़ना आवश्यक है। ऐसे में वहाँ पर छोटी कंपनियाँ भी अपने लिए कंसल्टेंट उपलब्ध करा लेती हैं। उक्त वक्तव्य जर्मनी के कोबलेन्ज चैंबर के प्रमुख पीटर रिचमैन ने आईआईए में आयोजित सेमिनार के दौरान व्यक्त की। देश की अग्रणी इंडस्ट्री संगठन आईआईए और जर्मनी के सेक्वा के संयुक्त तत्वावधान में संगठन के गोमनौनगर स्थित सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

लखनऊ

लखनऊ • बुधवार 12 दिसम्बर 2012

राष्ट्रीय स्वरूप

उद्यमियों को संगठित करने पर बल

लखनऊ (स्वरूप संवाददाता)। उद्यमियों को संगठित कर उन्हें नई तकनीकी के बारे में जागरूक करने के लिए जर्मनी के एक्सपर्टों ने पहल की है। इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आये विशेषज्ञों ने मंगलवार को राजधानी के गोमतीनगर में प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक की और अपने सुझाव दिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेट्री मनोप गोयल ने बताया कि इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा विविध जानकारी प्रदान की गयी।

‘उद्योगों के विकास में संगठनों का योगदान अहम’

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

‘इंडियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) की ओर से मंगलवार को ‘पब्लिक सपोर्ट फॉर इन्टरप्राइजेज कंसल्टेंसी ट्वर्ड्स इम जर्मनी’ विषय पर परिचर्या का आयोजन किया गया है। इसमें जर्मनी में औद्योगिक संगठन कैसे कार्य कर रहे हैं तथा उद्योगों की नइयतियों को दूर कैसे किया जाता है, इस पर एडवाइजरी सर्विस के विशेषज्ञ पीटर रिचमैन ने अपने विचार रखे।

रिचमैन ने कहा कि उनके देश में उद्योगों से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं

का क्रियान्वयन औद्योगिक संगठनों के माध्यम से ही होता है। औद्योगिक संगठन सरकार व उद्योगपति के बीच सेतु का कार्य करता है। वहां करीब एक करोड़ उद्योग हैं। उद्योगों का रजिस्ट्रेशन तभी हो पाता है जब वे किसी औद्योगिक संगठन से जुड़ जाते हैं।

उन्होंने भारत में औद्योगिक संगठनों को मजबूत करने की वकालत की। इस अवसर पर आईआईए के चेयरमैन प्रसान्त माटिया तथा निदेशक डीएस बर्मा समेत औद्योगिक क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद थे।